साप्ताहिक

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

RNI-MPHIN/2015/72544

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार 20-26 फरवरी, 2023, वर्ष-8, अंक-45

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठ :-8, मूल्य :- 2 रुपए

कुछ खास

- भारत कहता है जियो और जीने दो...वर्ष 2030 तक 345 मिलियन टन खाद्यान की मांग हो जाएगी
- अगर उत्पादन बढ़ाना है तो नए बीज पर अलग-अलग तकनीक का इस्तेमाल निरंतर करते रहना होगा
- मप्र का उत्पादन बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और कृषि डिजिटलकरण में नए आयाम बना रहे
- मप्र में कृषि ग्रोथ रेट 80 प्लस रही है, जो एक दशक से है, कृषि उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास किया
- अब 45 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो रही है, इसे 65 लाख हेक्टेयर तक ले जाने का प्रयास
- खेती को लाभ का धंधा बना रहे, जीरो प्रतिशत ब्याज पर किसानों को कर्ज मुहैया करवा रहे
- प्रकृति का दोहन न करें, जितना मिले उतना लें, कीटनाशक से पक्षियों की प्रजाति खत्म हो गई
- प्रदेश में 17.5 लाख हेक्टेयर में जैविक खेती हो रही, गोबर, गोमूत्र, केंचुआ से खाद बना रहे
- सैटेलाइट से मौसम का पूर्वानुमान और फसल हेल्थ कार्ड से किसानों की आय

सीएम शिवराज बोले- मप्र के 60 हजार किसानों कर रहे प्राकृतिक खेती

जी 20 बैठक: 100 प्रतिनिधियों ने किया मंथन

मध्यप्रदेश जैविकधानी

मैं खुद किसान हूं और महीन में एक बार अपने खेत पर जाता हूं दुनिया के खाद्यान की जरूरत पूरी करने हमें उत्पादन बढ़ाना होगा

इंदौर। जागत गांव हमार

इंदौर में आयोजित जी-20 की बैठक में 30 से ज्यादा देशों के 89 प्रतिनिधि शामिल हुए। तीन दिन विभिन्न देशों के प्रतिनिधि कृषि से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा कर प्रस्ताव तैयार किए। इसमें शामिल होने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इंदौर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने विदेशी मेहमानों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत की परंपरा है अतिथि देवो भव:। देश के सबसे स्वच्छ शहर में आपका स्वागत है। वसुदेव कुटुम्बक, सारी धरती एक परिवार है। हम सब एक एक है। यह सोच वर्षों से भारत की है।

मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि मध्यप्रदेश अब जैविकधानी भी बन गया है। राज्य में 60 हजार किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि खेतों में रसायन, हानिकारक कीटनाशकों के कारण बीमारियां बढ़ रही हैं। भूमि के भीतर रहने वाले कई जीव हानिकारक कीटनाशकों के कारण खत्म हो चुके है। इसलिए जैविक खेती आज की जरूरत है। मध्य प्रदेश जैविक खेती के मामले में देश में नंबर वन है। प्रदेश में 17 लाख हेक्टेयर में जैविक खेती हो रही है, जबकि 60 हजार किसानों ने प्राकृतिक खेती को अपनाया, हमारे युवा किसान जैविक खाद भी बना रहे है। गौमूत्र, गोबर से कीटनाशक बना रहे हैं। इससे धरती की सेहत भी सुधरेगी और मानव शरीर में भी पैष्टिक मिल रहा है।

मिलकर बढ़ानी होगी उत्पादकता

मुख्यमंत्री ने कहा कि लगातार जनसंख्या बढ़ने के कारण खाद्य सुरक्षा दुनिया के लिए महत्वपूर्ण विषय है,क्योंकि 2030 तक खाद्यान की मांग 345 मिलियन टन हो जाएगी, जबकि वर्ष 2000 में यह मांग 192 मिलियन टन थी। दुनिया में सिर्फ 12 प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है, उसको उपजाऊ बनाए रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। इस भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए।

स्मार्ट कृषि को अपनाना पड़ेगा

शिवराज ने कहा कि भारत में बड़ी आबादी कृषि कार्य करती है। मैं खुद किसान हूं और महीने में एक बार अपने खेत पर जाता हूं। यदि हमें दुनिया के खाद्यान की आवश्यकता पूरी करनी है तो हमें उत्पादन बढ़ाना होगा। नई तकनीक का इस्तेमाल, नए बीज, स्मार्ट एग्रीकल्चर को अपनाना पड़ेगा।

मंथन से निकलेंगे अच्छ निष्कर्ष

मप्र तिलहन और गेंहू का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश है,क्योकि सिंचाई का दायरा हमने बढ़ाया है। खेती को लाभ का धंधा बनाना होगा। इसलिए हम उत्पादन की लागत घटाने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों के लिए कई योजनाएं चलाई है। जीरो प्रतिशत ब्याज पर किसानों को कर्ज दिलाते हैं। जी-20 की बैठक में हुए मंथन से अच्छे निष्कर्ष निकलेंगे।

मिलेट्स को बढ़ावा देने में आगे मध्यप्रदेश

मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री की मंशा अनुसार मध्यप्रदेश मिलेट्स श्री अन्न को बढ़ावा देने में आगे है। आयरन और विटामिन से भरपूर मध्यप्रदेश के गेहूं और मिलेट्स के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी क्रम में एम्स भोपाल में भी मरीजों के लिए तैयार किए जाने वाले भोजन में मिलेट्स को शामिल करने की पहल हुई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्यप्रदेश का तेजस या कठिया गेहूं, कई राज्यों में जाता है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में इसकी विशेष मांग है। हाल ही में इंदौर में जी-20 की कृषि समूह की बैठक में भी प्रतिभागियों को मिलेट्स परोसे गए हैं।

देश में पहली बार

भोपाल वन विहार के 75 गिद्धों को लगाएंगे

भोपाल। जागत गांव हमार

देश में पहली बार मप्र के 40 गिद्धों पर पहली बार रखी जाएगी सैटेलाइट से नजर रखी जाएगी। ताकि उनके हर मूवमेंट की जानकारी लग सके। इन गिद्धों के अध्ययन के बाद अगले चरण में वन विहार के अंतर्गत आने वाले केरवा गिद्ध प्रजनन केंद्र में जन्में 75 गिद्धों को छोड़ा जाएगा। इन्हें छतरपुर में छोड़ा जाएगा। इससे पहले गिद्धों को पकाड़कर उन्हें सैटेलाइट ट्रांसमिशन डिवाइस लगाई जाएगी। इसके लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय इसके लिए काम करने वाली संस्था बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी को अनुमति दे दी है। वन विहार के गिद्ध ब्रीडिंग सेंटर में ब्रीडिंग से तैयार हुए लुप्त हो रहे लॉन्ग विल्ड वल्चर और व्हाइट बेक्ड गिद्ध प्राकृतिक रूप से अपना जीवन बिताने के लिए खुले में छोड़ा जाएगा।

प्रदेश के 40 गिद्धों में लगा रहे सैटेलाइट ट्रांसमिशन डिवाइस

वैज्ञानिकों ने लिया निर्णय

पन्ना नेशनल पार्क में गिद्धों के मूवमेंट पर रेडियो ट्रांसमिशन से नजर रखी जा रही है। कई रेडियो ट्रांसमिशन खराब हो गए तो कुछ ने सिग्नल नहीं दिए। रेडियो ट्रांसमिशन में आ रही समस्याओं को लेकर बीएनएचएस के वैज्ञानिकों ने निर्णय लिया है कि वन विहार गिद्ध सेंटर में जन्में गिद्धों को खुले में छोड़ने के पहले छतरपुर से लुप्त प्रजाति के गिद्धों को पकड़कर उन पर सैटेलाइट ट्रांसमिशन लगाकर अध्ययन किया जाए।

गिद्ध प्रजनन केंद्र से भेजा सैंपल

बीएनएचएस के अधिकारियों ने बताया कि गिद्ध के जन्म के बाद उसका डीएनए टेस्ट होता है। चूंकि ब्रीडिंग के वक्त इस बात का विशेष ख्याल रखा जाता है कि आपस में संबंध बनाने वाले गिद्ध कहीं भाई-बहन तो नहीं। बीएचएनएस ने 2016-2017 में वन विभाग और गिद्ध प्रजनन केन्द्रों की टीम ने मप्र, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ़ में सर्वे किया था। इसमें सामने आया कि इंटौविसक दवाओं का उपयोग हो रहा है। जिससे गिद्ध की किडनियां खराब हुई थीं।

एक गिद्ध पर सालाना 80 हजार

वन विहार के गिद्ध प्रजनन केन्द्र में एक गिद्ध पर सालभर में 80 हजार से ज्यादा का खर्च आ रहा है और गिद्धों को खुले आसमान में छोड़ने से पहले गिद्ध प्रजनन केन्द्र में पिंजरा बनाया हुआ है। ताकि वहां गिद्ध बाहरी माहौल महसूस कर सकें।

वन विहार के केरवा के गिद्ध सेंटर में लुप्त प्रजाति के लॉन्ग विल्ड वल्चर और व्हाइट बेक्ड गिद्ध हैं। इन्हें खुले में छोड़ने से पहले मप्र के गिद्धों के रहवास पर अध्ययन किया जाएगा। 40 गिद्धों को सैटेलाइट ट्रांसमिशन लगाया जाएगा।

-डॉ. विभाष पांडव, संचालक, बीएनएचएस

कृषि विशेषज्ञ ने कहा- किसान नमी रखनेकरे सिंचाई

फरवरी में गर्म हवाओं के झोंके घटेगा गेहूं का उत्पादन!

भोपाल। जागत गांव हमार

वर्तमान में उत्तर भारत में कोई मौसम प्रणाली सक्रिय नहीं है। राजस्थान और गुजरात में अधिकतम तापमान काफी बढ़े हुए हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक दक्षिणी राजस्थान पर एक प्रति चक्रवात बन गया है। इस वजह से राजस्थान और गुजरात की तरफ से आ रही गर्म हवाओं के कारण मध्य प्रदेश में तापमान बढ़ने लगा है। कृषि विशेषज्ञों ने तापमान बढ़ने के कारण गेहूं की फसल के समय से पहले पकने पर गेहूं की गुणवत्ता के साथ ही उत्पादन पर 10 प्रतिशत तक की कमी आने की आशंका जाहिर की है। साथ ही नुकसान से बचने के लिए किसानों को खेत में नमी बनाए रखने के लिए फसल में पानी देने की सलाह दी है।

...तो गेहूं का दाना पड़ जाएगा पतला

कृषि विशेषज्ञ एवं पूर्व कृषि संचालक डॉ. जीएस कौशल ने बताया कि अक्टूबर माह में भी वर्षा होने के कारण रबी की फसलों की बोवनी देर से की जा सकी थी। गेहूं की फसल में तापमान कम रहने से दाना पुष्ट होता है। वर्तमान में गेहूं की फसल को नमी की बेहद जरूरत है। पिछले तीन दिन से तापमान लगातार बढ़ रहा है। यदि मौसम का मिजाज लगातार इसी तरह बना रहा तो फसल समय पहले पक जाएगी। इससे गेहूं का दाना पतला रह जाएगा। इससे उत्पादन में 10 प्रतिशत तक की कमी आ सकती है।

शिवराज बोले-कृषि में सर्वाधिक उत्पादन के साथ नवाचारों में भी मध्यप्रदेश रिकॉर्ड बनाएगा

प्रदेश में अब नीला गेहूं शुगर फ्री आलू

विदेशियों को आकर्षित कर रहा प्रदेश का नीला गेहूं और शुगर फ्री आलू

भोपाल। जागत गांव हमार

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में अब नीला गेहूं भी हो रहा है और उसके निर्यात के ऑर्डर भी मिल रहे हैं। गेहूं निर्यात में मध्यप्रदेश नंबर एक है। अब काले गेहूं के बाद मध्यप्रदेश में नीले रंग का गेहूं भी पैदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि सीहोर का पीले और काले रंग के गेहूं के बाद अब नीले रंग का गेहूं है। ये बेकरी में उपयोग होता है। इसके निर्यात के आर्डर भी मिल रहे हैं। इसका पेटेंट करवाया गया था। उन्होंने कहा कि खेती में मध्यप्रदेश लगातार ना केवल आगे बढ़ रहा है, बल्कि कई तरह के प्रयोग भी कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जी-20 के कृषि समूह की बैठक में विभिन्न देशों से आए प्रतिनिधियों का प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में नीला गेहूं, शुगर फ्री आलू और बीज बैंक के रूप में हुए नवाचारों ने ध्यान आकर्षित किया है। हमारे किसानों द्वारा की गई यह पहल प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। बैठक में सम्मिलित होने के लिए देश के स्वच्छतम शहर इंदौर आये अतिथियों का भारतीय परम्परा के अनुसार स्वागत-सत्कार किया गया। हेरीटेज वॉक में अतिथियों ने हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सराहा है। मुख्यमंत्री श्यामला हिल्स स्थित उद्यान में पौधे लगाने के बाद मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश गेहूं निर्यात में पूरे देश में प्रथम है। साथ ही काले गेहूं के निर्यात के बाद अब नीले रंग के गेहूं का उत्पादन भी प्रदेश में शुरू हुआ है। बेकरी उत्पादों में काम आने वाले नीले गेहूं की मांग दूसरे देशों से भी आ रही है, इसका पेटेंट भी करा लिया गया है। सिमरौल की निशा पाटीदार ने विशेष प्रकार के शुगर फ्री आलू का उत्पादन आरंभ किया है। विलुप्त हो चुके मोटे अनाजों का बीज बैंक विकसित करने वाली डिंडोरी की लहरी बाई ने भी जी-20 सम्मेलन में अपना स्टॉल लगाया। श्री अन्न का यह बीज बैंक विदेशों से आए प्रतिनिधियों के आकर्षण का केन्द्र बन गया है। प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में नवाचार जारी हैं, इसमें भी हम रिकॉर्ड बनाएंगे।

केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने ड्रोन तकनीक व कृषि उड़ान योजना जैसे मुद्दों पर की चर्चा

विश्व को मिलेगी कृषि क्षेत्र के लिए नई राह

कृषि का क्षेत्र भारत के लिए सदैव अति महत्वपूर्ण रहा है और आगे भी रहेगा। 18 वर्षों में मप्र ने कृषि के क्षेत्र में तीव्रता हासिल की है। पहले प्रदेश में जहां सिंचाई का रकबा 200 लाख हेक्टेयर होता था, उसमें अब 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पहले मप्र में 165 लाख टन अनाज का उत्पादन होता था, जो अब 619 लाख टन हो गया है। प्रदेश सोयाबीन, दाल, लहसुन उत्पादन क्षेत्र में उभरा है और राष्ट्र के सबसे बड़े भू-उत्पादित राज्यों में शामिल है। ये बातें नागरिक एवं उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंदौर में जी-20 की बैठक के दूसरे दिन मीडिया से कही। उन्होंने कहा कि भारत जी-20 की अध्यक्षता कर रहा है। शुरुआती वर्किंग सेशन में अभी चर्चा होगी और इस मंथन से जो निचोड़ या अमृत निकलेगा, उसके आधार पर विश्व को कृषि के क्षेत्र के लिए नई राह मिलेगी।

अपनाना होगी थ्री एस स्ट्रेटजी

सिंधिया ने कहा कि भारत सबसे बड़े दुग्ध उत्पादक देश के रूप में उभर चुका है। फल व भाजी के क्षेत्र में दूसरे नंबर पर है। विश्व में तीसरे नंबर पर अनाज उत्पादन के क्षेत्र में है। पिछले आठ वर्षों में अनाज उत्पादन में 265 मिलियन टन से 315 मिलियन टन तक पहुंच चुके हैं। हमारी सोच और विचारधारा का असर है कि विगत आठ वर्षों में कृषि बजट का आउटलेट साढ़े चार गुना करीब साढ़े 10 बिलियन डालर हो चुका है। हमारी सोच है कि कृषि के इको सिस्टम के लिए वैश्विक स्तर पर थ्री एस एस स्ट्रेटजी को अपनाया जाए।

थ्री एस स्ट्रेटजी

स्मार्ट: ड्रोन तकनीक को इस्तेमाल करके कृषकों के कार्यों के लिए सहूलियत हो रही है। उन्हें स्वास्थ्य की सुविधा प्राप्त हो रही है। उत्पादन में बढ़ोतरी हो सकती है।

सस्टेनेबल: प्रत्येक किसान को अपने खेत की उत्पादन क्षमता बढ़ाने में सहयोग, टेक्नोलाजी व मार्केटिंग के लिए इनपुट देने का प्रयास।

सर्व: भारत की हजारों साल पुरानी मोटे अनाज की संस्कृति है। इसका लाभ पोषण व पर्यावरण के तरीके से एक-एक मनुष्य को मिले। इसका व्यापक प्रचार-प्रसार सिर्फ देश के लिए नहीं, वैश्विक स्तरपर किया जाएगा।

डिंडोरी की रहने वाली लहरी बाई ने बताए मोटे अनाज के फायदे, कर रहीं बीज संरक्षण

मैं और मेरे माता-पिता पिछले कई वर्षों से कोदो, कुटकी, बजारा जैसे मोटे अनाज का सेवन कर रहे हैं। हम आज तक बीमार नहीं हुए और न ही अस्पताल जाकर इलाज करवाने या डॉक्टर से सुई लगवाने की जरुरत पड़ी। ये बातें डिंडोरी के सिलपिड़ी गांव की रहने वाली 27 वर्षीय लहरी बाई ने खास चर्चा में बताई। वे जी 20 कृषि समूह बैठक के अवसर पर इंदौर पहुंचीं थीं। लहरी बाई को मिलेट्स का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। इसके अलावा बीज बैंक बनाने के लिए पीएम मोदी ने भी उनकी तारीफ की है। लहरी बाई बताती हैं कि उनकी दादी काफी समय से अपने खेती के माध्यम से घर में मोटे अनाजों का संरक्षण करती थी। दादी द्वारा किए गए काम को ही वो आगे बढ़ा रही है।

वर्तमान में लहरी बाई के पास 50 से 60 प्रकार की मोटे अनाज और 60 से 70 प्रकार के हरी सब्जियों की प्रजातियां हैं। वे अपने क्षेत्र के 25 गांवों के करीब 450 किसानों को नि:शुल्क अनाज के बीज उपलब्ध करवाती हैं। जब किसान की नई फसल आ जाती है तो वो खुद ही लहरी बाई को एक किलो बीज के बदले में डेढ़ किलो अनाज बीज के रूप में दे जाते हैं। इससे लहरी उन बीजों को अन्य किसानों को देती हैं। सिलपिड़ी गांव में लहरी के पास चार से पांच एकड़ की जमीन है। इस पर वे बिना ट्रैक्टर या उपकरण के शून्य प्रसंस्करण विधि से खेती करती हैं। वे अपनी खेती में गोबर की खाद व घर के गीले कचरे से बनी खाद का उपयोग करती हैं।

ग्लोबल ड्रोन हब में विकसित होगा भारत

कृषि व अन्य क्षेत्रों में ड्रोन तकनीक पर सिंधिया बोले कि 2050 में भारत विश्व में ग्लोबल ड्रोन हब के रूप में विकसित होगा। मंत्रालय ने पिछले डेढ़ साल में इसके लिए काफी प्रयास किए हैं। रजिस्ट्रेशन के साथ नई ड्रोन पालिसी भी बनाई गई है। डिजिटल मैप बनाया गया है। इस उद्योग के प्रमोशन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। पीएसआइ स्कीम के माध्यम से 120 करोड़ तक इंसेंटिव भी दिए गए हैं, उद्योग विकसित होगा। केंद्र व राज्य सरकारों को इसके लिए मांग पैदा करनी होगी। भविष्य में कृषि, पशुधन, पेस्टिसाइड, ग्रामीण विकास, खनन उद्योग सहित 12 तरह के क्षेत्रों में ड्रोन का उपयोग तेजी से बढ़ेगा। इसके लिए पालिसी भी बनाई जा रही है। अगले पांच दशक में ड्रोन इंडस्ट्री 60 करोड़ तक की होगी। ड्रोन का उपयोग सीडबाल, कीटनाशक छिड़काव व दवाओं को दूर-दराज के इलाकों तक पहुंचाने में किया जाएगा।

21 नए हवाई अड्डे जोड़े जाएंगे

सिंधिया ने बताया कि सरकार देश के 21 नए हवाई अड्डों को कृषि उड़ान योजना से जोड़ने की तैयारी में हैं। इससे कृषि, बागवानी, मत्स्य उत्पादों का तेज गति से हवाई परिवहन सुनिश्चित हो सकेगा। अभी देश में 31 हवाई अड्डे कृषि उड़ान योजना से जुड़े हैं।

जाने खेती के तरीके, मांडू का भ्रमण कर हुए अभिभूत

-उन्नत कृषक द्वारा पाली हाउस में की जा रही खेती देखी

धार के सिलोटिया गांव पहुंचा विदेशी मेहमानों का दल

किसान ने ककड़ी और प्याज की फसल से कमाया मुनाफा

धार। जी-20 शिखर के मेहमान पर्यटन नगरी मांडू जाने के पहले जिले के ग्राम सिलोटिया पहुंचे। यहां दल के सदस्यों ने उन्नत कृषक लखन रामेश्वर पटेल का पाली हाउस देखा। उन्होंने उद्यानिकी एवं वानिकी विभाग योजनांतर्गत पाली हाउस भी देखा। कृषक रमेश पटेल से पाली हाउस से की गई खेती के बारे में जानकारी ली। विदेशी दल के मेहमान यहां पाली हाउस में हो रही ककड़ी की खेती को देखकर काफी प्रभावित हुए। ग्राम सिलोटिया में 30 से अधिक किसानों ने साफा पहनाकर विदेशी मेहमानों की अगवानी की। करीब 15 से अधिक महिला प्रतिनिधि मंडल ने भी महिला मेहमानों की भी अगवानी की। विदेशी मेहमानों को गुलाब के पुष्पगुच्छ भेंट किए गए। सिलोटिया पहुंचने पर ग्रामीणों द्वारा भारतीय संस्कृति अनुसार तिलक लगाकर विदेशी मेहमानों का स्वागत-सत्कार किया गया। निर्धारित कार्यक्रम अनुसार दल के सदस्यों को मांडू पहुंचना था, लेकिन दोपहर करीब तीन बजे उनका सिलोटिया में किसान के खेत पर जाने का कार्यक्रम तय होने से गांव में चर्चा का विषय बना रहा। बड़ी संख्या में विदेशी मेहमानों को देखने किसान व महिला-पुरुष एकत्रित हो गए थे।

उन्नत कृषक की सफलता की कहानी

उन्नत कृषक लखन बीते पांच वर्ष से ककड़ी की खेती ले रहे हैं। यहां से मध्यप्रदेश के अलावा अन्य राज्यों हरियाणा, जयपुर, राजस्थान व गुजरात में भी ककड़ी की फसल निर्यात करते हैं। उन्नत कृषक लखन ने बताया कि एक एकड़ खेत में उन्होंने पाली हाउस लगाया है। पाली हाउस के पहले उन्हें इतना उत्पादन नहीं हो पाता था। पाली हाउस लगाने के बाद बेहतरीन उत्पादन कर परिवार का जीवन निर्वाह कर रहे हैं।

यह रहे मौजूद: इस दौरान कलेक्टर प्रियंका मिश्रा, एसपी आदित्य प्रताप सिंह, कृषि विभाग के उपसंचालक ज्ञान सिंह मोहनिया सहित जनपद उपाध्यक्ष दिलीप डाबर, सरपंच लीलाबाई, वरिष्ठ कृषक दिलीप पटेल, उपसरपंच पीयूष सोनगरा, दिलीप जाट, आत्माराम सोनगरा, राजेंद्र सोनगरा, परमानंद चौधरी, भारत टेलर आदि मौजूद थे।

मांदल की थाप पर थिरके अतिथि

अतिथियों का कारवां लंबा था। आगे पीछे गाड़ियों की रेलम पेल थी। जी-20 के सभी प्रतिनिधि 2 बसों के माध्यम से मांडू पहुंचे। लगभग 80 से भी ज्यादा अतिथि मांडू दर्शन करने पहुंचे। यहां मांदल की थाप पर और बांसुरी की तान पर रंग बिरंगी परंपरागत वेशभूषा पहने आदिवासी नर्तक दलों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान मेहमान बेहद खुश नजर आए और कई मेहमान तो मांदल की थाप पर अपने आप को नृत्य करने से भी नहीं रोक सके।

-विदेश तक पहुंच रहे हमारे उत्पाद

मोटे अनाज की खेती अब लाभ का धंधा

मोटा अनाज कई सालों से निर्यात किया जा रहा है। अब तक उपज को ही सीधे बेचा जा रहा था मगर अब वैश्विक बाजार पर पकड़ बनाने के लिए मिलेट्स से बने उत्पाद की ब्रांडिंग हो रही है। विदेश में प्रदर्शनी लगाकर मिलेट्स से बने रेड टू ईट और रेडी टू सर्व श्रेणी के कुकीज, नूडल्स, पास्ता सहित बेकरी के उत्पाद का प्रमोशन किया गया। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) दुनिया में मोटे अनाजों के निर्यात को बढ़ावा देने के प्रयास में जुटा है। एपीडा के मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ रीजनल हेड सौरभ अग्रवाल ने बताया कि विश्व में मोटे अनाज उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 41 प्रतिशत है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में 159,332.16 टन मोटे अनाज का निर्यात किया गया, जबकि वित्तीय वर्ष 2020-21 में 147,501.08 टन निर्यात हुआ था। वित्तीय वर्ष 2022-23 में इसे बढ़ाने के लिए मोटे अनाज के प्रोडक्ट भी वैश्विक बाजार में उतार रहे हैं। एपीडा के रीजनल हेड अग्रवाल का कहना है कि इस वर्ष दक्षिण अफ्रीका, यूएई, जर्मनी, नेपाल, सऊदी अरब, ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देशों में प्रमोशन के लिए एक्सपो में शामिल होकर मोटे अनाज और उनके प्रोडक्ट की ब्रांडिंग की जाएगी।

उत्पादन का राज्यवार प्रतिशत

राजस्थान	39
उत्तरप्रदेश	20
हरियाणा	12
गुजरात	11
मध्य प्रदेश	07
महाराष्ट्र	05
तमिलनाडु	02

वित्तीय वर्ष 2021-22 में इन देशों में हुआ निर्यात

देश	निर्यात
मिस्र	350
जर्मनी	2739
यूएसए	3309
ईरान	4601
जापान	6107
ओमान	6297
बांग्लादेश	7812
सऊदी अरब	20154
यूएई	33394
अन्य देश	51240
कुल	159332

मिट्टी की कोठियों में रखती हैं बीज

सिलपिड़ी गांव दो कमरों के मिट्टी के घर में एक कमरे में वे अपने माता-पिता के साथ रहती हैं और उसमें ही किचन बना हुआ है। दूसरे कमरे में 15 मिट्टी कोठियां बनी हैं। जिसमें सीडबैंक है। इसमें सभी प्रजातियों के बीजों को सहेजकर रखा जाता है।

बीज संरक्षण के लिए शादी नहीं की

लहरी के माता- पिता काफी बुजुर्ग हैं। ऐसे में उनकी जिम्मेदारी लहरी ही उठा रही है। इसके अलावा वे अपनी दादी व माता-पिता द्वारा मोटे अनाज के बीजों के संरक्षण के लिए काम कर रही हैं। यही वजह है कि वो शादी नहीं करना चाहती ताकि दोनों काम को कर सकें।

जीआई टैगिंग लेने का प्रयास

जवाहरलाल नेहरु कृषि विवि और मप्र के कृषि विभाग ने लहरी बाई के पास कोदो और कुटकी के बीजों को लेकर उससे नई वैरायटी बनाई है। इसमें कोदो जेके 9-1 व कुटकी जेके-95 नई प्रजातियां विकसित की गई हैं। इसके अलावा लहरीबाई के पास उपलब्ध नामदमन कुटकी, सिताही कुटकी लेकर जीआई टैग हासिल किया है। जीआई टैगिंग होने यहां के किसानों को लाभ मिल सकेगा।

मुख्यमंत्री के पौध-रोपण की गूंज लोकल से ग्लोबल स्तर तक

जलवायु परिवर्तन तथा ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव के इस दौर में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रतिदिन पौध-रोपण से देश-विदेश में मध्यप्रदेश का नाम पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध एक ब्राण्ड के रूप में स्थापित हुआ है। देश-विदेश में जब संगोष्ठियों, सेमीनारों और पर्यावरणीय विमर्श में जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों की रोकथाम पर महज अकादमिक चर्चा हो रही है, तब शिवराज सिंह चौहान ने इस संबंध में व्यक्तिगत स्तर पर कर्म करने का प्रण लिया। यह प्रण था प्रतिदिन स्वयं पौधा लगाने का और उपक्रम में लोगों को जोड़ने का। दो साल पहले मुख्यमंत्री ने मां नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक में 19 फरवरी 2021 को नर्मदा जयंती के अवसर पर प्रतिदिन पौधा लगाने की शुरूआत की उसे वे दो वर्ष बाद भी निरंतर रखे हुए हैं।

सर्दी, गर्मी, बरसात जैसे मौसम के बदलाव हों या स्वयं के स्वास्थ्य की समस्याएं, या फिर मुख्यमंत्री के दायित्व निर्वहन की व्यस्तताएं और प्रदेश व प्रदेश के बाहर के प्रवासों की उलझनें, कोई भी स्थिति उन्हें प्रतिदिन पौध-रोपण के अपने प्रण से डिगा नहीं पाई। श्री चौहान ने इन दो वर्षों के 730 दिनों में लगभग 2200 पौधे लगाए। पौधे लगाने की गतिविधि का विस्तार प्रदेश सहित देश के 12 राज्यों तक हुआ। अब स्थिति यह है कि मुख्यमंत्री श्री चौहान के साथ प्रतिदिन कई सामाजिक संगठन और व्यक्ति, स्व-प्रेरणा से पौध-रोपण कर रहे हैं। यही वजह है कि बिन्दु से आरंभ हुआ सामाजिक सरोकार का यह प्रयास सिंधु बनने की ओर निरंतर अग्रसर है।

मुख्यमंत्री चौहान की अपील का प्रदेशवासियों पर होता है आत्मीय प्रभाव: मुख्यमंत्री श्री चौहान, मुख्यमंत्री होने के साथ-साथ जन-जन के सर्वमान्य नेता, प्रदेश के बच्चों के मामा, बहनों के भाई और प्रदेश के परिवेश में रचे-बसे जननायक हैं। प्रदेशवासियों पर उनकी हर अपील का आत्मीय प्रभाव होता है। श्री चौहान ने पौध-रोपण के अपने प्रण से जन-जन को जोड़ने के लिए लोगों को अपने जीवन के महत्वपूर्ण अवसरों जन्मदिवस, विवाह वर्षगांठ तथा अपने परिजनों की स्मृतियों को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए उनकी पुण्य-तिथि पर पौधे लगाने का आहवान किया है। उनके आहवान के परिणामस्वरूप राजधानी भोपाल सहित पूरे प्रदेश में पौध-रोपण की गतिविधि को विस्तार मिला। देश-दुनिया जब कोरोना से प्रभावित थी तब भी उस काल में कोरोना से बचाव की सावधानियों के साथ पौध-रोपण जारी रहा। कोरोना के नियंत्रण में आने के साथ ही, जनवरी 2022 से श्यामला हिल्स स्थित स्मार्ट सिटी उद्यान में मुख्यमंत्री के साथ अपने जन्मदिवस, विवाह वर्षगांठ या परिजनों की स्मृति में पौधे लगाने के लिए आने वाले लोगों की संख्या बढ़ती चली गई। जनवरी 2022 से अब तक 1600 से अधिक व्यक्तियों ने उनके साथ पौधे लगाए।

पौधा लगाने वाले अपने योगदान को डिजिटल स्वरूप में रखते हैं सुरक्षित: पर्यावरण संरक्षण के पावन कार्य में जन-सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रदेश में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने एक और नई पहल की है। यह पहल है विश्व पर्यावरण दिवस 05 जून 2021 से आरंभ किया गया प्रदेशव्यापी अंकुर कार्यक्रम। इसके तहत लोग पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण के महायज्ञ में अपने योगदान को डिजिटल स्वरूप में सुरक्षित रख सकते हैं। इसके लिए वायुदूत एप पर रजिस्ट्रेशन कराकर स्वयं के द्वारा लगाए गए पौधे की फोटो अपलोड करने की व्यवस्था है। पौधा लगाने के बाद उसकी देख-रेख की जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिभागियों के लिए निश्चित समयावधि के बाद पुन: फोटो अपलोड करने के साथ ही चयनित लोगों को प्राण वायु अवार्ड से सम्मानित करने की व्यवस्था भी है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने भी लगाया भोपाल में पौधा: श्री चौहान ने प्रत्येक प्रमुख अवसर पर अपने पौध-रोपण के प्रण को पूरी प्रभावशीलता के साथ प्रकट किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने स्वयं भोपाल के स्मार्ट सिटी उद्यान में बरगद का पौधा लगाया। राज्यपाल मंगुभाई पटेल, मुख्यमंत्री श्री चौहान तथा केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा भी राष्ट्रपति के साथ पौध-रोपण में शामिल हुए और पीपल तथा कचनार के पौधे लगाए। राष्ट्रपति मुर्मु द्वारा मध्यप्रदेश की पावन धरती पर पौध-रोपण के लिए उनका आभार मानते हुए मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा था कि इससे हमारे उस अभियान को बल मिला है।

मुख्यमंत्री के साथ देश-विदेश के लोगों ने किया है पौध-रोपण: हाल ही में मध्यप्रदेश को कई प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों की मेज़बानी का अवसर प्राप्त हुआ। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में जहाँ देश-विदेश के प्रमुख उद्योगपति और निवेशक मध्यप्रदेश में आए, वहीं विदेश मंत्रालय द्वारा इंदौर में आयोजित 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन में गुयाना गणराज्य के राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद इरफ़ान अली, सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिकाप्रसाद संतोखी तथा विश्व के लगभग सभी प्रमुख देशों में फैले प्रवासी भारतीय, मध्यप्रदेश आये। खेलो इंडिया यूथ गेम्स-2022 का आयोजन प्रदेश के सात शहरों, जी-20 के कृषि कार्य समूह बैठक का आयोजन इंदौर में और जी-20 के ही थिंक-20 की बैठक भोपाल में हुई। साथ ही भारत सरकार द्वारा वॉटर विज़न समिट और अन्य राष्ट्रीय स्तर की बैठकें प्रदेश में आयोजित की गई। इन आयोजनों में देश-विदेश से आए प्रतिनिधि मंडलों के सदस्य और गणमान्य नागरिकों ने मुख्यमंत्री श्री चौहान की पर्याज्वरण-संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता को देखकर स्वयं आगे आते हुए भोपाल और इंदौर में पौध-रोपण में शामिल हुए। परिणामस्वरूप मुख्यमंत्री श्री चौहान के प्रतिदिन पौध-रोपण के प्रण की गूँज लोकल से कहीं आगे जाकर ग्लोबल स्तर तक हो रही है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान के साथ हार्ट फुलनेस संस्थान के वैश्विक अध्यक्ष परम पूज्य दाजी कमलेश पटेल, सदगुरु जग्गी वासुदेव ने भी पौधे लगाए। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण कार्यक्रमों के कार्यकारी निदेशक रहे एरिक सॉल्हिम, साउथ अफ्रीका टूरिज्म की हब प्रमुख नेलिस्वा जकाबी, विज्ञापन जगत की जानी-मानी हस्ती पद्मश्री पीयूष पाण्डेय, कश्मीर फाईल्स के निदेशक विवेक अग्निहोत्री, फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार सहित खेल, कला-संस्कृति, शिक्षा जगत और राजनैतिक क्षेत्र के लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भी मुख्यमंत्री श्री चौहान के साथ पौधरोपण किया।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अन्य राज्यों में भी रोपे हैं पौधे: मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश के बाहर प्रवास के दौरान गुजरात के भरूच स्थित मनन आश्रम, तमिलनाडु के गोड़ादेवी मंदिर, हरिद्वार, वाराणसी, शिर्डी, नासिक, चिन्नाजीयर स्वामी आश्रम हैदराबाद, माँ त्रिपुर सुंदर मंदिर त्रिपुरा, कान्हा शांति वनम, हार्टफुलनेस संस्थान हैदराबाद, माँ अमृतानंदमयी मठ परिसर केरल, पुदुचेरी और चैन्नई सहित अन्य स्थानों में भी पौधे लगाकर प्रतिदिन पौधे लगाने के अपने प्रण को निरंतर रखा है।

पशु-पक्षी एक प्राकृतिक आपदा संकेतक

» डॉ. विपिन कुमार गुप्ता
» डॉ. प्रीती गुप्ता
» डॉ. एसपीएस परिहार
» डॉ. अनुराधा बुधोलिया
» डॉ. बीएससी. रेड्डी

पशु जन स्वास्थ्य एवं महामारी विज्ञान विभाग, पशु चिकित्सा एवं पशु पालन महाविद्यालय,महू।

प्राकृतिक आपदा, पकृति की ऐसी घटनाएं जैसे भूकम्प, सुनामी, अतिवृष्टि, बादल फटना, बाढ़, अनावृष्टि; सूखा, चक्रवात, तूफान, इत्यादि। जो कि विनाश के कारक हैं। जिनसे मानव जीवन एवं उसके अस्तित्व पर खतरा आता है जिसमे शारीरिक, मानसिक प्रताड़ना के साथ-साथ हजारों, लाखों जानों का नुकसान होता है। इससे मानव की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक गतिविधियों पर असर पड़ता है एवं वह कई दशक पीछे धकेल दी जाती हैं। यही प्राकृतिक आपदा कहलाती है। पशु-पक्षी हमारे सच्चे, वफादार साथी होने के साथ-साथ अपने शरीर के विभिन्न उत्पादों एवं स्वंय को भोज्य पदार्थ के रुप मे देकर हमारी जीवनपर्यन्त सेवा करते है।

प्राचीन काल से ही मानव सभ्यता पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर रही है। पहले मानव अपने क्रिया-कलापों से प्रकृति के निकट वास करता था। प्रत्येक घर मे भोजन सम्बधी, कृषि सम्बधी, परिवहन सम्बधी, सुरक्षा सम्बधी, इत्यादि आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पशु-पक्षियों का पालन होता था। पशु-पक्षियों मे कुछ विशिष्ट शक्तियां पाए जाने के कारण ये एक प्राकृतिक आपदा सकेंतक-तंत्र का कार्य करते थे। जब कभी भी प्राकृतिक आपदा और विपत्ति आती तो इस सकेंतक तंत्र से जुड़े रहने के कारण मनुष्य को इनका पूवार्नुमान हो जाता था। आधुनिक काल में मानव ने धरती पर विकास के नये-नये कीर्तिमान स्थापित किए हैं। जैसे- ग्रामीण जीवन शैली से शहरी जीवन शैली के रूपांतरण। जैविक कृषि पद्धति से रासायनिक कृषि पद्धति अपनाने में। पशु पालन की आद्यव्यवस्था से पशुरहित जीवन शैली की ओर अग्रसर होने में। विकास की इस दौड़ में मानव प्रकृति से पूर्णत: कट गया। एक ओर जहां पशु-पक्षी अपने जीवन मे प्रकृति की विपरीत परिस्थितियों मे छठी इन्द्रियों का उपयोग भली भाँति कर लेते हैं, वहीं दूसरी ओर मनुष्य का प्रकृति से पृथ्वक्करण उसे भारी विपदा एवं नुकसान की ओर धकेल देता है। पशु-पक्षी प्राकृतिक आपदा से पूर्व ही विभिन्न ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा विपदाओं के आगमन को पहचान लेते हैं। तत्पश्चात संकेतक एवं सूचक के रुप मे विभिन्न मुद्राओं एव ध्वनियों को प्रदर्शित करते हैं। **जैसे** -

प्राकृतिक आपदा से पूर्व पालतू पशु-पक्षियों के द्वारा स्वतंत्र होने की कोशिश करना। प्राकृतिक विपदा से पहले ही पशु-पक्षियों का अपने आवास स्थानों से बदहवास होकर इधर-उधर भागना या उड़ना। आपदा से पूर्व जोर-जोर से शोर करना। जैसे-पक्षियों का क्रन्दन करना, कुत्तों का भौंकना एवं अपने मालिक को पकड़कर सुरक्षित स्थान की ओर खीचंना। चीटियों, चूहों, सापों, एवं अन्य बिलों मे रहने वाले जानवरों का उनसे बाहर निकल आना एवं सुरक्षित स्थानों की ओर जाना।

तथ्य से जुड़े हुए कुछ सन्दर्भ-1. भुज (गुजरात) का भूकम्प - सन्दर्भित घटना स्वयं एक लेखक के साथ घटित हुई, जिसमें की भूकम्प के झटकों का असर एक बड़े भू-भाग मे महसूस हुआ। उस समय लेखक राजस्थान मे था सुबह का समय था। वह बिस्तर पर लेटा हुआ था बाहर जोर-जोर सें कुत्तों का शोर सुबह की प्यारी नींद मे व्यवधान डाल रहा था तभी अचानक कमरे में ऊपर रखी हुई चीजें नीचे गिरने लगीं। कुछ समझ पाता उससे पहले ही बाहर कॉलोनी मे भगदड़ मचने लगी। भूकम्प की आवृत्ति का सबको अनुभव हो चुका था। बाद में इसी भूकम्प से सम्बधित एक घटना का पता चला कि एक पालतू कुत्ते ने अपनी महिला मालिक को साड़ी पकड़ कर भवन से बाहर खींचा। तत्पश्चात् बाहर निकलते ही वह भवन भर -भराकर गिर गया लेकिन वह कुत्ता एवं उसकी महिला मालिक सुरक्षित बच गयें।

2. जूनागढ़ (गुजरात) का भूकम्प शाम का समय था लेखक बाहर कृषि विश्वविद्यालय के गार्डन मे घूम रहा था। अचानक से पक्षियों का चहचहाना चालू हो गया। झुण्ड बनाकर वह चिल्लाते हुए उड़ रहे थे। सारे प्राणी इधर-उधर भागने लगें। लेखक तत्पश्चात पास ही गार्डन की कुर्सी पर बैठ गये। अचानक ही पत्थर की घरेलू आटा चक्की जैसी चलने की आवाज हुई एवं सब कुछ हिलने लगा। सभी लोग घरों से बाहर आ गए। पता चला भूकम्प आया था।

3. श्रीलंका, सुमात्रा, अण्डमान-निकोबार एवं दक्षिण भारत की सुनामी- श्रीलंका एवं सुमात्रा में आई सुनामी की एक घटना का संदर्भ है। वहा के सरकारी समाचार के अनुसार कुछ मानवीय नुकसान अवश्य हुआ, परन्तु कोई पशु-पक्षी नहीं मरा। जबकि समुद्री लहरें मुख्य जगल मे अन्दर तक आ गई थी। जानवर निम्न स्थानों को छोड़कर ऊच्च स्थानों की ओर पलायन कर गए थे। समुद्र किनारे सैर करने वाले जानवरों ने तटों पर जाना छोड़ दिया। कुत्ते इत्यादि जानवर ऊंचाई वाले स्थानों पर चले गये। अण्डमान-निकोबार द्वीप समूह मे कोई भी स्वस्थ पशु नहीं मरा, ज्यादातर पशु सुनामी से पूर्व ही ऊंचाई वाले स्थानों पर चले गए थे।

यद्यपि विज्ञान छठीं इंद्री के विषय मे अनभिज्ञता व्यक्त करता है। परन्तु इस तथ्य को पूर्णतया नकारा नहीं जा सकता है। पशु-पक्षी प्राकृतिक आपदाओं के अतिरिक्त मानवजन्य आपदाओं को भी पुर्वानुमानित कर लेते हैं। ऐसे प्रमाण भी दृष्टिगत हैं जानवर संभवतया हवा में दबाव की स्थितियों मे परिवर्तन एवं अपने शरीर की ज्ञानेंद्रियों से, आने वाली आपदा को अनुमानित कर लेते हैं तथा एक विशिष्ट, अद्भुत एवं आश्चर्यजनक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। लेखक का मानना है कि पशु-पक्षियों का प्रकृति के निकट विभिन्न स्थितियों में रहना एवं जीवन की विपरित परिस्थितिओ मे जीनें के अनुकूल रास्ता बनाना जो कि प्रकृति प्रदत्त है, उनकी इस अद्भुत शक्ति का मुख्य कारण है।

32.3 करोड़ टन को पार कर सकता है खाद्यान्न उत्पादन

कृषि वर्ष 2022-23 में प्रमुख खाद्यान फसलों में बंपर उत्पादन का अनुमान है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम अनुमान से पता चला है कि इस साल खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 32.3 करोड़ टन को पार कर सकता है। जो पिछले वर्ष 2021-22 की तुलना में 79.38 लाख टन अधिक है।

सरकार ने इसका श्रेय मेहनतकश किसानों और वैज्ञानिकों की कुशलता को दिया है। हालांकि सरकार ने इसके लिए अपनी पीठ थपथपाते हुए किसानों को ध्यान में रखकर बनाई नीतियों को भी वजह माना है। इस बाबत जो सरकारी आंकड़े जारी किए हैं उनके अनुसार गेहूं, चावल, मक्का, चना, मूंग, रेपसीड, सरसो और गन्ने में रिकॉर्ड उत्पादन का अनुमान है। पता चला है कि 2022-23 में चावल का कुल उत्पादन रिकॉर्ड 13.08 करोड़ टन होने का अनुमान है जोकि पिछले साल की तुलना में 13.65 लाख टन ज्यादा है। इसी तरह सरकार ने गेहूं उत्पादन में भी रिकॉर्ड वृद्धि का अनुमान लगाया है, जिसके 11.2 करोड़ टन से ज्यादा रहने की सम्भावना है। देखा जाए तो देश में पिछले साल की तुलना में इस बार 44.4 लाख टन ज्यादा गेहूं पैदा हो सकता है। बेहतर मौसम के कारण फसल की पैदावार अच्छी होने की उम्मीद है।

केंद्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने अग्रिम अनुमानों में मोटे अनाज के उत्पादन में दिखती वृद्धि की सराहना करते हुए आशा जताई कि आने वाले वर्षों में इनका उत्पादन और उपयोग बढ़ सकता है। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2023 को अंतराष्ट्रीय मोटे अनाज के वर्ष के रुप में मनाने की घोषणा की है। वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी मोटे अनाज 'श्री अन्न' का नाम दिया है।

गेहूं, धान, मक्का, गन्ना आदि का हो सकता है रिकॉर्ड उत्पादन

इसी तरह 2022-23 मक्के का उत्पादन रिकॉर्ड 346.13 लाख टन पर पहुंचने का अनुमान है, जो पिछले साल की तुलना में करीब 8.83 लाख टन अधिक है। वहीं यदि मोटे यानी पोषक अनाज जिसे सरकार ने श्रीअन्न का नाम दिया है उसका उत्पादन 527.26 लाख टन रहने का अनुमान है, जो पिछले साल की तुलना में करीब 16.25 लाख टन ज्यादा है।

इसी तरह मूंग का उत्पादन भी 35.45 लाख टन के नए रिकार्ड पर पहुंचने की सम्भावना जताई गई है, जो पिछले वर्ष हुई पैदावार की तुलना में 3.8 लाख टन ज्यादा है। गौरतलब है कि 2022-23 के दौरान दलहन का कुल उत्पादन 278.1 लाख टन रहने की सम्भावना जताई है, जोकि पिछले साल की तुलना में 5.08 लाख टन और पिछले पांच वर्षों के औसत दलहन उत्पादन की तुलना में 31.54 लाख टन अधिक रहने की सम्भावना है। इसी तरह सोयाबीन और सरसों का उत्पादन क्रमश: 139.75 लाख और 128.18 लाख टन रहने के अनुमान है, जो पिछले साल 2021-22 के उत्पादन की तुलना में क्रमश: 9.89 लाख टन और 8.55 लाख टन ज्यादा है।

-11 करोड़ टन से अधिक होगा उत्पादन

देश में गेहूं पैदावार में टूटेगा रिकॉर्ड, मप्र में घट गया रकबा

भोपाल। जागत गांव हमार

देश में इस बार रिकॉर्ड क्षेत्र में गेहूं की बोवनी हुई है तो वहीं गेहूं के रिकॉर्ड उत्पादन की संभावना भी विशेषज्ञों ने जताई है। इस साल 11.20 करोड़ टन से अधिक गेहूं का उत्पादन हो सकता है। वहीं मप्र में किसानों का गेंहूं की खेती से मोहभंग हो गया है। आंकड़ों पर गौर करें तो पता चलता है कि इस साल मध्यप्रदेश में गेहूं का रकबा अप्रत्याशित रूप से घटा है। इस रबी सीजन में गेहूं का रकबा लगभग चार लाख 15 हजार हेक्टेयर कम हुआ है। गौरतलब है कि मप्र को कृषि कर्मण अवार्ड दिलाने में गेहूं के उत्पादन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लेकिन इस बार प्रदेश के किसानों में गेहूं की खेती पर अधिक जोर नहीं दिया है। हालांकि रबी फसलों के जो मौजूदा आंकड़े सामने आ रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार, किसान, कारोबारी, आमजन सभी को राहत दी है। केंद्र सरकार इसलिए खुश है कि बंपर उत्पादन से देश में घरेलू खपत का संकट नहीं होगा। वहीं, अच्छे उत्पादन से किसानों की इनकम बढ़ जाएगी। आमजन को सस्ती दरों पर आटा मिलेगा तो कारोबारी भी अधिक गेहूं बेचकर अच्छी आय कमा सकेंगे। लिहाजा गेहूं उत्पादन के लिहाज से ये साल सभी के लिए अच्छा होना वाला है। इस बार राजस्थान में 2.52 लाख हेक्टेयर, महाराष्ट्र 1.03 लाख हेक्टेयर, उत्तर प्रदेश 93 हजार हेक्टेयर, बिहार 94 हजार, गुजरात 43 हजार हेक्टेयर, छत्तीसगढ़ 47 हजार हेक्टेयर, जम्मू कश्मीर 9 हजार, असम में 3 हजार हेक्टेयर में गेहूं की बुवाई की गई है। विशेष बात यह है कि इन सभी राज्यों में गेहूं का रकबा बढ़ा है। केंद्र सरकार इन आंकड़ों से खुश है।

11.20 करोड़ हो सकता है उत्पादन

देश में इस बार 11.20 करोड़ टन गेहूं उत्पादन होने की उम्मीद है। पिछले साल के सापेक्ष इस साल देश में रबी फसलों का रकबा बढ़ गया है। देश में 720.68 लाख हेक्टेयर में फसल बोई गई है, जबकि वर्ष 2021-22 में इसी पीरियड में रबी फसलों का रकबा 697.98 लाख हेक्टेयर था। आंकड़ों को ही देखें तो पिछले साल और साल में करीब 23 लाख हेक्टेयर में रबी फसलों की ग्रोथ दर्ज की गई है। बुवाई में ये वृद्धि 3.25 प्रतिशत है। गेहूं उत्पादन के मामले में भारत विश्व के अग्रणी देशों में हैं। पिछले साल भी भारत ने गेहूं उत्पादन में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। गेहूं का उत्पादन 10.95 करोड़ टन उत्पादन हुआ था। लेकिन इस बार जो गेहूं उत्पादन की स्थिति दिख रही है। उसमें उत्पादन का पिछला सारा रिकॉर्ड ध्वस्त होता दिख रहा है। इस बार गेहूं का उत्पादन 11 करोड़ टन के पार जा सकता है।

यहां घट गया गेहूं का एरिया

केंद्र सरकार की ओर से जो आंकड़ें सामने आए हैं। उनके अनुसार, पिछले साल गेहूं 341.84 लाख हेक्टेयर में गेहूं की बुवाई की गई थी। लेकिन लू चलने के कारण इसके उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई थी। वहीं सरकार इस साल रिकॉर्ड बुवाई की उम्मीद जता रही थी। बुवाई के आंकड़ों को देखें तो केंद्र सरकार की उम्मीदों को पंख लगे हैं। इस बार 343.23 लाख हेक्टेयर हो चुकी है। देश में करीब 1.39 लाख हेक्टेयर बुवाई का रकबा बढ़ गया है। ऐसा नहीं है कि सभी राज्यों में गेहूं बुवाई का क्षेत्र बढ़ा है। देश में काफी ऐसे भी राज्य हैं, जहां गेहूं का रकबा बहुत तेजी से घटा है। जिन राज्यों में घटत दर्ज की गई है। उनमें मध्य प्रदेश में 4.15 लाख हेक्टेयर, झारखंड 31 हजार, पंजाब 18 हजार, हरियाणा 11 हजार, हिमाचल 10 हजार, पश्चिम बंगाल 9 हजार, उत्तराखंड 2 हजार, कर्नाटक 2 हजार हेक्टेयर शामिल हैं। यहां पिछले साल गेहूं बुवाई का ग्राफ बढ़ा हुआ था।

सेहत की खातिर-अशोक नगर से सभी धर्मों के लोगों ने पैसे और सामग्री देकर तैयार कराए

गायों की इम्युनिटी बढ़ाने मैथी, अजवाइन और सोंठ के सात क्विंटल लड्डू मंगाए

भोपाल। जागत गांव हमार

राजधानी की सड़कों पर घूमने वाले आवारा गौवंश को इन दिनों कुछ पशुप्रेमी पौष्टिक लड्डू खिलाते नजर आ रहे हैं। यह लड्डू मैथी, अजवाइन, सोंठ, आमी हल्दी, खोपरा और सरसों के तेल समेत अन्य औषधीय पाउडर को गुड़ और चुनी में मिलाकर तैयार किए गए हैं। इसका फायदा ये है कि गाय इनको खाकर न सिर्फ सर्दी से बचेगी, बल्कि रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी। ये जिम्मा पशुप्रेमी प्रमांशु रंजन शुक्ला, निधि वर्मा और मनीषा मालवीय समेत अन्य ने उठाया है। पशुप्रेमियों द्वारा मंगाए सात क्विंटल लड्डुओं में से पिछले पांच दिनों में पांच क्विंटल पौष्टिक लड्डू गोवंश को खिलाए गए हैं।

तीन साल से बन रहे लड्डू-

गायों को खिलाए जा रहे इन पौष्टिक लड्डुओं को अशोक नगर निवासी गो सेवक सोनू जैन के प्रयासों से बनवाए गए हैं। सोनू तीन साल से तमाम धर्मों के लोगों को साथ लेका यह कार्य कर रहे हैं। लड्डू बनाने के लिए सभी धर्मों के लोग सामग्री तो कुछ पैसा दान के तौर पर देते हैं। इस पैसे से बनाए गए लड्डू सोनू अलग-अलग शहरों के गो सेवकों को उपलब्ध कराते हैं। ताकि, गायों को यह सर्दी में खिलाए जा सकें।

मुफ्त 7 क्विंटल लड्डू भोपाल भेजे

पशुप्रेमी प्रमांशु ने बताया कि मुफ्त 7 क्विंटल से ज्यादा लड्डू आए हैं। 10 से ज्यादा पशु प्रेमियों की मदद से जहांगीराबाद स्थित आसरा पशु आश्रय स्थल में कमजोर और बीमार पशुओं के साथ सड़कों और कांजी हाउस में रखे जा रहे गोवंश को यह लड्डू खिलाएं जा रहे हैं। निधि वर्मा ने बताया कि अशोक नगर में सामाजिक लोगों की मदद से हर साल पौष्टिक लड्डू बनवाते हैं। वहां से लड्डू भोपाल भेजे गए हैं।

65 क्विंटल बन गए

सोनू ने बताया कि इस साल हमने 50 क्विंटल पौष्टिक लड्डू बनाने का टारगेट रखा था। इसी हिसाब से समाज के लोगों से मदद करने के लिए प्रयास किए गए। लेकिन, लोगों ने उम्मीद से भी ज्यादा मदद की और सामग्री उपलब्ध कराई। ऐसे में जो सामग्री हमको मिली उससे 65 क्विंटल पौष्टिक लड्डू तैयार हुए हैं। इनको अशोक नगर के गोवंश को खिलाने के साथ ही भोपाल, सागर, विदिशा और गुना समेत अन्य शहरों को भी भेजा गया है।

हर घर नल से जल पहुंचेगा

वित्त मंत्री देवड़ा बड़नगर में विकास यात्रा में हुए शामिल

भोपाल। वित्त एवं वाणिज्यिक कर, आर्थिक सांख्यिकी एवं उज्जैन के प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा ने उज्जैन जिले के बड़नगर ग्राम पंचायत में विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमि-पूजन किया। साथ ही जल जीवन मिशन के कार्यों का निरीक्षण किया। मंत्री ने कहा कि जिले के सभी ग्रामों में हर घर नल से जल पहुंचेगा। सरकार ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। किसी को दूर से जल नहीं लाना पड़ेगा। देवड़ा विकास यात्रा के दौरान ग्राम पंचायत पलवा एवं सिजवता में मुख्यमंत्री जन-सेवा अभियान में हितग्राहियों को स्वीकृति-पत्र प्रदान किए। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के नेतृत्व में प्रदेश का विकास अनवरत जारी है। उन्होंने बताया कि विकास यात्रा 25 फरवरी तक जारी रहेगी। यात्रा के दौरान गांव-गांव जाकर ऐसे पात्र व्यक्तियों का चिन्हित किया जाएगा जिन्हें अभी शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल है। ऐसे सभी पात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ दिलवाया जायेगा। विकास यात्रा में के दौरान उज्जैन सांसद जन-प्रतिनिधि एवं अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

गौशाला का संचालन नहीं होने से बढ़ी समस्या

15 लाख से बनाई गौशाला पांच साल से बंद

रामपुरकलां। जागत गांव हमार

रामपुरकलां में गौशाला का संचालन नहीं होने से आवारा मवेशी किसानों की मूंग व सब्जी की फसल को उजाड़ रही हैं। कहने को पंचायत मुख्यालय पर गौशाला का निर्माण है लेकिन उसमें चारा व भूसा उपलब्ध न होने के कारण ग्राम पंचायत आवारा मवेशी को रखने से दूरी बनाए है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से गौशाला का नियमित संचालन करने की मांग की है। किसानों का कहना है कि ग्राम पंचायत रामपुरकलां में पंच परमेश्वर योजना के तहत वर्ष 2017 में 14 लाख 92 हजार रुपए की लागत से गौशाला का निर्माण कराया गया। गौशाला का लोकार्पण पूर्व विधायक मेहरबान सिंह रावत ने 18 सितंबर 2017 को किया था। इसके बाद गौशाला का संचालन केवल 8 माह हो पाया। इन 8 माह में भी गौशाला का संचालन ग्रामीणों से चंदा एकत्रित कर किया गया। इसके बाद बजट के अभाव के चलते गौशाला में जो गाय थीं उन्हें छोड़ दिया गया और गोशाला बंद हो गई। जबकि गौशाला खाली होने से

गौवंश किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहा है। ग्रामीणों की मांग है कि फसलों को सुरक्षित रखने के लिए जल्द ही गौशाला का संचालन शुरू किया जाए।

चारागाह कराए जा रहे तैयार

जिला पंचायत सीईओ डॉ. इच्छित गढ़पाले का कहना है कि गौशालाओं का संचालन ऑटोनॉमस मोड में कराने की तैयारी है। इसके लिए स्व-सहायता समूहों को गौशालाओं की कमान सौंपी जा रही है। वहीं गौवंश को भरपूर भोजन मिल सके, इसके लिए गेशालाओं से लगी जमीन पर चारागाह विकसित किए जा रहे हैं। वहीं समूहों के माध्यम से गौवंश से प्राप्त होने वाले गोबर आदि से तमाम तरह के आयटम तैयार कर मार्केटिंग की तैयारी भी है।

सामाजिक संस्थाएं आगे आएं मदद के लिए

गौशालाओं के संचालन के लिए पूरी तरह सरकार पर निर्भर नहीं होना चाहिए। सामाजिक संस्थाओं को भी आगे आने की जरूरत है। यदि एक व्यक्ति एक गाय के लिए 10 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जनभागीदारी हो जाए, तो साल में 3650 रुपए होते हैं। इसके लिए गो- संवर्धन बोर्ड ने ऑनलाइन दान की व्यवस्था की है।

बजट-150 करोड़ से मात्र 60 करोड़ किया

कमलनाथ सरकार ने 2018 में गोशालाओं के लिए 150 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया था। जबकि 2021-22 में शिवराज सरकार ने 60 करोड़ का ही प्रावधान किया। यानी सरकार चाहे कांग्रेस की हो या भाजपा की, दोनों ने ही गौशालाओं की जरूरत के मुताबिक बजट नहीं दिया। प्रदेश में अभी 627 प्राइवेट और मुख्यमंत्री गौसेवा योजना से बनी 951 गौशालाओं में करीब 2 लाख 55 हजार से अधिक गाय हैं। इनके साल भर खाने के लिए ही करीब 184 करोड़ की आवश्यकता है, लेकिन सरकार की ओर से इतना बजट कभी दिया ही नहीं गया। मुरैना जिले की बात करें तो 9 गौशालाओं को सरकार की तरफ से अनुदान मिल रहा है लेकिन वहां आवारा गौवंश नहीं रखा जा रहा है।

-लोगों ने मनरेगा में पांच एकड़ में 10 हजार पौधे लगाए

मनरेगा से एक सुंदर और अनोखी वाटिका बनाई

खरगोन। जागत गांव हमार

जिला मुख्यालय से सात किमी ठिबगांव। दो वर्ष पहले कोरोना संक्रमण के कारण लगे लॉकडाउन में मियावाकी पद्धति से हुआ पौधरोपण अब घना जंगल बन गया है। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए इंदौर, गुजरात, महाराष्ट्र से लौटे ग्रामीणों ने मनरेगा में काम किया। इसमें तालाब, पौधारोपण आदि काम हुए। यहां गांव में पौधारोपण किया और 10 हजार पेड़ बन गए। यह जंगल उनकी ही देन है। ठिबगांव के सचिव महेंद्र यादव ने बताया कि किसी समय यह पूरा पांच एकड़ का क्षेत्र उजाड़ और बेजान पड़त भूमि हुआ करता था। मनरेगा में मियावाकी पद्धति से 10.25 लाख की लागत से वर्ष 2021-22 में पौधारोपण किया गया था। अब यहां ग्राम विकास में मनरेगा से एक सुंदर और अनोखी वाटिका बनाई गई है। यहां की हर शाम अब बुजुर्गों के लिए फुरसत का वक्त बिताने में गुजरती है। मनरेगा से बनाई गई माधव वाटिका गांव के लिए एक सुंदर और रमणीय स्थल बन गया है। वाटिका बनते बनते ही यहां रोज 8 से 10 बुजुर्ग वॉकिंग के लिए पहुंचने लगे हैं। हाल ही में इस वाटिका को विकास यात्रा के दौरान गांव के लिए समर्पित किया गया है।

पैवर निर्माण और पेंटिंग कर रही आकर्षित

वाटिका को मनरेगा और 15 वें वित्त मद से 3.57 लाख रुपए से सुंदर और आकर्षक बन गई है। इसमें पेबर ब्लॉक और सुंदर पेंटिंग किसी नेशनल पार्क या विहार सा अहसास कराती है। अब ये गांव का एक मुख्य रूप से घूमने फिरने का स्थल बन रहा है। इसी के पास स्वच्छता के लिए 7.99 लाख रुपए का सेग्रीगेशन शेड बनाया गया है। सचिव महेंद्र यादव ने बताया कि इस पौधारोपण की दो अलग-अलग साइट पर 1032 और 1400 मानव दिवस तक काम चला। इसमें 277 मजदूरों में 22 पलायन करने वाले श्रमिक शामिल थे।

मियावाकी पद्धति में जल्द बढ़ते हैं पौधे

मियावाकी एक जापानी पद्धति है। इस पद्धति में बहुत कम समय में जंगलों को घने जंगलों में परिवर्तित किया जा सकता है। इस पद्धति में देशी पद्धति में देशी प्रजाति के पौधे एक दूसरे के समीप लगाए लाते हैं। जो कम स्थान घेरने के साथ ही अन्य पौधों में वृद्धि में भी सहायक होते हैं। सघनता के कारण पौधे सूर्य की रोशनी को धरती पर आने से रोकते हैं। जिससे खरपतवार नहीं उग पाती। तीन वर्षों के बाद पौधों की देखभाल की आवश्यकता नहीं होती। इस पद्धति में मुख्य रूप से झाड़ी छोटे पेड़, पेड़ और कैनोपी प्रकार के पौधे लगाएं जाते हैं। पौधारोपण से पूर्व मिट्टी में बायोमास मिलाया जाता है, जो मिट्टी की जल धारण क्षमता व पोषक तत्वों को बढ़ाने में मदद करता है।

पौधे कराते हैं ताजगी का अहसास

मियावाकी तकनीक से यहां 10 हजार पौधे रोपे गए थे। खुशी की बात है कि पूरे पौधे जीवित है। यहां निमाड़ का पेड़ नीम तो है ही इसके साथ नींबू, सीताफल, इमली, सुरजना सुबबूल के अलावा जामुन और करंज लगाए हैं। इसके पास वर्षों पुराना तालाब भी अनुपम है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा शुरू किए व्यक्तिगत पौधारोपण की दूसरी वर्षगांठ पर यहां 8 हजार पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है।

-सीएम बोले-जनजातीय समाज को विकास की दौड़ में पीछे नहीं रहने देंगे

-पेसा नियम संबंधी जिला एवं ब्लॉक समन्वयक प्रशिक्षण कार्यशाला

पेसा एक्ट को अच्छे से पढ़ कर गांव-गांव में समझाएं

भोपाल। जागत गांव हमार

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पेसा नियम कोई कर्म-कांड नहीं है, यह जनजातीय भाई-बहनों की जिंदगी बदलने का अभियान है। जनजातीय समाज भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। विकास की दौड़ में उन्हें पीछे नहीं रहने दिया जाएगा। मेरे मन में विकास की बुनियादी जरूरतें सड़क, बिजली, पानी की सुविधाएं देने और जीवन की स्थिति को बेहतर बनाने की तड़प थी। जनजाति वर्ग के विकास के लिए विभिन्न पहलुओं का ध्यान रखा जा रहा है। मुख्यमंत्री बरखेड़ीकलां स्थित क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज प्रशिक्षण केंद्र में पेसा नियम संबंधी जिला एवं ब्लॉक समन्वयक प्रशिक्षण एवं कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे खुशी है कि आपने बेहतर शिक्षा प्राप्त करने के बाद पेसा को-आर्डिनेटर बनने का मन बनाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर क्षेत्र में तेजी से प्रगति हो रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री भू-अधिकार और लाड़ली लक्ष्मी योजना सहित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में लाड़ली बहना योजना बनाई गई है। कुपोषण का स्तर घटाने और बहनों को सशक्त बनाने में यह योजना कारगर सिद्ध होगी। इस योजना में गरीब परिवार की बहनों के खाते में एक हजार रूपए महीना देंगे। बहनें सशक्त होंगी तो परिवार, प्रदेश और देश सशक्त होगा। लोगों की जिंदगी बदलने के लिए ही पेसा नियम बनाया गया है। जनजातीय भाई-बहनों की जमीन अब छल-कपट से कोई हड़प नहीं सकेगा। बाहर से आने वाले लोगों को ग्रामसभा में जानकारी देना होगी। जनजातीय वर्ग का वनोपज पर हक होगा तो उनका आर्थिक सशक्तीकरण भी होगा।

प्रशिक्षित और प्रोत्साहित करें

मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यशाला के प्रतिभागी अन्य लोगों को प्रशिक्षित और प्रोत्साहित करें। पेसा नियमों को ढंग से पढ़ कर गांव में लोगों को समझाएं। उन्होंने कहा कि यह अपने हक और समाज को जोड़ने का अभियान है। युवाओं की ताकत खड़ी करनी है। आपको मौका मिला है तो मन में तड़प और ललक के साथ कार्य करें। इससे बड़ा पुण्य का कार्य कोई नहीं है। पेसा के साथ अन्य योजनाओं को भी आप समझ लें, जिससे लोगों को समझा सकें।

आदिवासियों को दूंगा गाय-भैंस

सीएम ने कहा कि हमने तय किया है कि बैगा, भारिया, सहरिया जनजाति के लोगों को गाय और भैंस दी जाएंगी, योजना में 90 प्रतिशत राशि सरकार देगी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की इस कार्यशाला में 14 जिला और 70 ब्लॉक समन्वयक शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने सभी जिला समन्वयकों का परिचय प्राप्त किया। मुख्यमंत्री ने पूछा कि पेसा कोआर्डिनेटर बनने के पीछे आपकी सोच क्या है। प्रशिक्षणार्थियों ने अपने विचारों से अवगत कराया।

-16वें दीक्षांत समारोह में कृषि मंत्री ने कहा

जवाहरलाल नेहरू कृषि विवि का इतिहास स्वर्णिम

भोपाल। किसान-कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल आज जबलपुर के जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के 16वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय का इतिहास स्वर्णिम रहा है। मध्यप्रदेश के सबसे पुराने जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय ने कृषि संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। दीक्षांत समारोह में कुलपति, प्राध्यापक, कृषि वैज्ञानिक, और विद्यार्थी मौजूद रहे। कृषि मंत्री ने दीक्षांत समारोह में शामिल सभी मेधावी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश की उन्नत कृषि और प्रदेश को लगातार मिलने वाले कृषि कर्मण पुरस्कारों में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय का अहम योगदान है। यहाँ अध्ययन करने वाले सभी विद्यार्थी स्वयं को गौरवान्वित समझें कि वे उत्कृष्ट और बेहतर संस्थान में अध्ययन कर रहे हैं। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि विवि में अध्ययन के साथ ही सांस्कृतिक, खेलकूद और व्यक्तित्व विकास के लिए भी समुचित प्रयास किए जाते हैं, जिसकी ख्याति पूरे देश में व्याप्त है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय देश के विकास में एक नई इबारत लिख रहा है। यहाँ के विद्यार्थी दीक्षित होने के बाद उन्नत कृषि में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि भविष्य में विश्वविद्यालय के विद्यार्थी कृषि क्षेत्र में आने वाली समस्या एवं चुनौतियों का हल ढूंढने में भी समर्थ रहेंगे।

-मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा

खाद्य सुरक्षा में भारत और मध्यप्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है आज दुनिया में खाद्य सुरक्षा सबसे जरूरी है। वर्ष 2030 तक दुनिया की खाद्य आवश्यकता 345 मिलियन टन हो जाएगी। दुनिया की खाद्य सुरक्षा में भारत और भारत में मध्यप्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान होगा। आज भारत स्वयं के साथ ही विश्व की खाद्यान आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। अकेले मध्यप्रदेश ने इस वर्ष 21 लाख मीट्रिक टन गेहूं का आयात किया है। पिछले 18 वर्षों में मध्यप्रदेश में बुआई रकबे एवं उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। प्रदेश में 18 वर्ष पहले बोवनी का रकबा 199 लाख हेक्टेयर था, जो आज बढ़ कर 299 लाख हेक्टेयर हो गया है, वहीं उत्पादन 169 लाख मीट्रिक टन से बढ़ कर 619 मीट्रिक टन हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में भारत का पूरी दुनिया को सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का संदेश है। हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को रहने लायक बनाये रखना है। हम जैविक खेती और प्राकृतिक खेती के पक्षधर हैं। मध्यप्रदेश में बड़ी संख्या में किसान प्राकृतिक खेती को अपना रहे हैं। रासायनिक खाद और कीटनाशकों का उपयोग मानव स्वास्थ्य के लिए तो गंभीर खतरा है ही, इससे पर्यावरण एवं जीव-जंतुओं को भी अत्यधिक नुकसान हो रहा है। इससे कई प्रजातियां नष्ट हो रही हैं।

भारत मोटा अनाज वर्ष मना रहा

मुख्यमंत्री ने कि कहा इस वर्ष भारत मोटा अनाज वर्ष मना रहा है। दुनिया में आज मोटे अनाज की मांग तेजी से बढ़ रही है। कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा, रागी जैसे मोटे अनाज प्राकृतिक खेती से आसानी से हो जाते हैं और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं। प्रदेश में बड़ी मात्रा में मोटा अनाज होता है। हम मोटे अनाज की राजधानी हैं। प्रदेश में मिलेट मिशन भी चलाया जा रहा है। देश की खेती उत्तम है। देश में प्राकृतिक खेती के साथ ही खेती के क्षेत्र में आधुनिक तकनीक का उपयोग भी किया जा रहा है। स्वाईल हेल्थ कार्ड बनाए जा रहे हैं। मध्यप्रदेश का शरबती गेहूं और चित्रौर चावल दुनिया में धूम मचा रहे हैं।

दक्षिण अफ्रीका से लाए 12 चीतों को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बाड़े में कराया प्रवेश

चीता प्रोजेक्ट वन और वन्यप्राणी बचाने के साथ दिलाएगा आदिवासियों को रोजगारः शिवराज

श्योपुर। जागत गांव हमार

चीता प्रोजेक्ट वन और वन्यप्राणियों को बचाने के साथ-साथ ग्रामीणों को भी रोजगार मुहैया कराएगा। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कूनो रेस्टहाउस पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहीं। वह शनिवार को दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 12 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में शिफ्ट कराने पहुंचे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 5 माह पहले कूनो अभ्यारण्य में 8 चीतों की सौगात दी, जिसका असर प्रदेश के साथ-साथ देश में होगा। एशिया महाद्वीप में सिर्फ भारत में ही अब चीतें हैं। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात हैं। चीतों के कूनो में आने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। सीएम ने दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 12 चीतों को कूनो सेंचुरी में बनाए गए क्वारंटीन बाड़े में छोड़ा। अब कूनो में चीतों की कुल संख्या 20 हो गई है। इनमें 10 नर और 10 मादा हैं। इससे पहले पिछले साल सितंबर में 8 चीते नामीबिया से लाए गए थे। 12 चीतों की शिफ्टिंग के दौरान सीएम चौहान के साथ केन्द्रीय मंत्री एवं स्थानीय सांसद नरेन्द्र सिंह तोमर, केन्द्रीय वन मंत्री भूपेन्द्र सिंह यादव, प्रदेश के वनमंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह आदि मौजूद थे। चीता छोड़ने आए मुख्यमंत्री ने चीता मित्र और कुल्हाड़ी-तीर कमान समर्पण करने वालों से भी मुलाकात की और उनके हौंसले की प्रशंसा करते हुए कहा कि, आपका हृद्य परिवर्तन ही वन और वन्य प्राणियों को बचाएगा।

चीता मित्र व कुल्हाड़ी तीर कमान समर्पण करने वालों से की चर्चा

चीतों को कूनो में शिफ्ट कराने पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कूनो रेस्टहाउस पर चीता मित्रों और कुल्हाड़ी एवं तीर कमान समर्पण करने वालों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने कलेक्टर शिवम वर्मा के विकास यात्रा में पर्यावरण संरक्षण के लिए किए गए नवाचार की प्रशंसा की। ज्ञातव्य हो कि, कराहल विकासखंड में विकास यात्रा के दौरान जंगल से लकड़ियां काटने वाले लकड़हारे व शिकार करने वाले मोगिया जनजाति के लोगों द्वारा तीर कमान समर्पण कर रहे हैं। इनमें से बरगवां और कराहल के आदिवासियों से कलेक्टर ने मुलाकात कर उनके कुल्हाड़ी और तीर कमान समर्पण की प्रशंसा करते हुए कहा कि, आपकों इस त्याग बड़ा फल मिलेगा। चीता श्योपुर जिले के साथ-साथ प्रदेश और भारत की पहचान भी विश्वभर में पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ाएगा, जिसका सबसे अधिक असर आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ने वाला हैं।

होमस्टे योजना से जुड़ेंगे आदिवासी

सीएम चौहान ने आदिवासियों को होमस्टे योजना से जोड़कर उनकी आर्थिक स्थिति को बढ़ाने की बात कहीं। उन्होंने कहा कि, चीता आने से प्रदेश और देश का नाम भी पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ा हैं। उन्होंने कहा कि, पूरे एशिया महाद्वीप में सिर्फ भारत ही एक देश हैं, जहां चीते बसते है, उसमें भी मप्र और प्रदेश के श्योपुर जिले का कूनो अभ्यारण्य शामिल है। चीतों की वजह से यहां पर्यटन तेजी से बढ़ेगा, जिसके लिए चीता प्रोजेक्ट तैयार किया गया हैं। पर्यटकों को ठहराने के लिए गांवों में होमस्टे के तहत ग्रामीणों के आवास तैयार किए जाएंगे, ताकि देशी-विदेशी सैलानियों को आश्रय के साथ-साथ वनों में बनी आदिवासियों की झोपड़ियों में ठहराने का रोमांच भी महसूस हो सके। इससे आदिवासियों की आय कई गुना बढ़नी तय हैं।

सीएम ने जारी किया सासा का मेडिकल बुलेटिन

कूनो पहुंचे मुख्यमंत्री ने पूर्व में छोड़े 8 चीतों के इंक्लोजर का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों से चीतों के बारे पूरी जानकारी ली। बाद में पत्रकारों के सामने सीएम ने बताया कि, जो मादा चीता (सासा) कुछ समय पहले बीमार हो गई थी, वह अब पूरी तरह स्वस्थ हैं। कूनो का वातावरण नामीबिया से लाए चीतों को रास आ गया है। कूनो का समतल और घास से छिपा मैदान चीतों प्रजाति के लिए मुफीद हैं। अफ्रीके चीतें भी जल्द ही इस वातावरण में रम जाएंगे।

सीएम ने जताया पीएम नरेंद्र मोदी का आभार

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने चीतों को कूनो में छोड़ने भोपाल से रवाना होने से पहले ट्वीट कर चीतों को पुनर्वास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। उन्होंने ट्वीट किया कि मध्यप्रदेश में चीतों का स्वागत है। चीतों का पुनर्वास पर्यटन और रोजगार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विलुप्त हुए चीतों का पुनर्स्थापन एशियमा महाद्वीप, भारत और भारत में भी मध्यप्रदेश में किया है। पूरा प्रदेश उनका आभार प्रकट कर रहा है। पहले आए चीते पूर्णतः स्वस्थ हैं।

कूनो के प्रवेशद्वार पर वन कर्मियों से उलझे भाजपाई

चीतों को शिफ्ट कराने पहुंचे मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में कुछ भाजपा नेता वनकर्मियों से उस समय उलझ गए, जब वनकर्मियों ने उन्हें कूनो के प्रवेशद्वार पर ही रोक दिया। एक भाजपा नेता वनकर्मी को विधायक की धमकी देकर रौब झाड़ रहा था, लेकिन वनकर्मी ने भी स्पष्ट कह दिया कि मैं तुम्हारे विधायक के नीचे काम नहीं करता। मेरी ड्यूटी इस गेट पर लगाई हैं। विधायक को गेट से प्रवेश कराना था, वह सीएम के साथ चले गए हैं। जिसके पास प्रवेश पास हैं वहीं प्रवेश करेगा।

स्व सहायता समूह की महिलाओं से मिले सीएम

चीतों को बाड़े में छोड़ने के बाद सीएम ने स्वसहायता समूह की महिलाओं से मुलाकात की। यहां महिलाओं ने सीएम को जुड़ीबूटियों का रक्षा सूत्र बांधा और लाड़ली बहना योजना लागू करने के लिए धन्यवाद दिया। इस बारे में बताते हुए सीएम ने ट्वीटर पर लिखा, यह डोर है विकास की, यह डोर है विश्वास की, यह डोर है प्रेम और आस की। लाडली बहना योजना को लेकर बहनें जिस आत्मीयता, प्रेम, स्नेह और उल्लास के साथ अपनी भावनाओं का प्रकटीकरण कर रहीं हैं, उससे मन अत्यंत गदगद और भावविभोर हो रहा है।

-दो दिवसीय प्रशिक्षण वैज्ञानिकों ने बताया कैसे और क्यों करें खेती, मिट्टी व जलवायु पर पड़ने वाले दुष्परिणामों से अवगत कराया गया

लंबी आयु और स्वस्थ जीवन के लिए करनी होगी प्राकृतिक खेती

टीकमगढ़।

कृषि विज्ञान केंद्र टीकमगढ़ में प्राकृतिक खेती पर दो दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण डॉ. बीएस किरार, डॉ. आरके प्रजापति, डॉ. एसके सिंह, डॉ. यूएस धाकड़, डॉ. आईडी सिंह, हंसनाथ खान और जयपाल छिगारहा द्वारा दिया गया। डॉ. बीएस किरार ने प्रशिक्षण के दौरान प्राकृतिक खेती एवं रासायनिक युक्त खेती में अंतर को समझाया और वर्तमान में प्राकृतिक खेती की आवश्यकता क्यों पड़ रही है और रासायनिक युक्त खेती का मानव स्वास्थ्य, मिट्टी, जलवायु की गुणवत्ता पर पड़ने वाले दुष्परिणामों से अवगत कराया गया। उन्होंने बताया कि मनुष्य को लंबी आयु और स्वस्थ जीवन के लिए प्राकृतिक खेती करना जरूरी है। साथ ही प्रत्येक परिवार को खुशी

के अवसरों पर फलदार या ईमारती पौधों का रोपण करना चाहिए। हर किसान परिवार को एक संकल्प लेना चाहिए कि हमें आज से ही अपने परिवार की पूर्ति के लिए रसायन मुक्त सब्जी, अनाज एवं फल उत्पादन करने का प्रयास शुरू करेंगे। डॉ. आरके प्रजापति ने प्राकृतिक खेती अंतर्गत फसलों और सब्जियों में कीट-व्याधियों के प्रबंधन अंतर्गत अग्नेयास्त्र, नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र एवं दशपर्णी आदि का घोल बनाना व उनके उपयोग के बारे में बताया।

प्रशिक्षणार्थियों को प्रदर्शन प्लाटों में समन्वित कीट प्रबंधन अंतर्गत प्रकाश प्रपंच, पीली एवं नीली पट्टिका, फल मक्खी डिब्बा, फेरोमेन ट्रैप एवं टी आकार की खूटियों के उपयोग एवं उनके द्वारा नियंत्रण होने वाले कीटों के बारे में बताया गया। डॉ. एसके सिंह ने बताया कि प्राकृतिक खेती से पोषण वाटिका में सब्जियों एवं फलों का उत्पादन कर रसायन मुक्त उत्पादन करें, जिससे लागत में भी कमी आयेगी और उत्पादन गुणवत्तापूर्ण स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक प्राप्त होगा। डॉ. यूएस धाकड़ द्वारा प्राकृतिक खेती के घटकों बीजामृत, जीवामृत, घनजीवामृत, संजीवक, आच्छादन, अंतरवर्तीय खेती, वाफसा आदि के बनाने की विधि-उपयोग का समय व प्रति एकड़ मात्रा के उपयोग के बारे में बताया गया। बीजामृत घोल तैयार कर बीजों का उपचार करना बहुत जरूरी है। बीजामृत द्वारा शुद्ध बीज जल्दी एवं अच्छी मात्रा में अंकुरित होते हैं और जड़ें तेजी से बढ़ती हैं। साथ ही बीज एवं भूमि द्वारा फैलने वाली बीमारियां रुकती हैं और पौधे की वृद्धि अच्छी होती है।

जीवामृत घोल को सिंचाई के साथ दें

जीवामृत एक एकड़ जमीन के लिए देशी गाय का गोबर 10 किग्रा, देशी गाय का मूत्र 8-10 लीटर, गुड़ 1-2 किग्रा, बेसन 1-2 किग्रा, पानी 180 लीटर और पेड़ के नीचे की 1 किग्रा मिट्टी, आदि सामग्रियों को एक प्लास्टिक ड्रम में डालकर लकड़ी के एक डंडे से हिलाकर घोलना चाहिए। इस गोल को 2-3 दिनों तक छाया में सड़ने के लिए रख देना चाहिए। दिन में 2 बार डंडे से घड़ी की सुई की दिशा में घोल को 2 मिनट तक घुमाना चाहिए। जीवामृत घोल को बोरे से ढक कर रख देना चाहिए। जीवामृत घोल को गर्मी में 7 दिनों तक और सर्दियों में 10-15 दिनों तक उपयोग में लाया जा सकता है। जीवामृत घोल को सिंचाई के साथ देना चाहिए।

आईसीएआर ने पशुधन नस्लों के पंजीकरण के लिए हितधारकों को सम्मानित किया

पशुओं की देशी नस्लों की पहचान जरूरी: नरेन्द्र सिंह तोमर

जागत गांव हमार, नई दिल्ली।

केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि देश में बड़ी संख्या में देशी नस्ल के पशु हैं, जिनकी पहचान सभी क्षेत्रों में करने की जरूरत है। इससे कृषि और पशुपालन क्षेत्र की समृद्धि में मदद मिलेगी।

श्री तोमर ने राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केन्द्र, नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) द्वारा आयोजित पशु नस्ल पंजीकरण प्रमाणपत्र वितरण समारोह में अपने संबोधन में यह बात कही। श्री तोमर ने अपने संबोधन में कहा, देश का आधा पशुधन अभी भी अवर्गीकृत है। हमें जल्द से जल्द ऐसी अनूठी नस्लों की पहचान करनी होगी, ताकि इन अवर्गीकृत नस्लों को बचाया जा सके। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि आईसीएआर इस दिशा में काम कर रहा है और देश में ऐसी नस्लों की पहचान के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया गया है।

श्री तोमर ने देश के विभिन्न हिस्सों से नई नस्लों के सभी आवेदकों की सराहना करते हुए कहा कि ये देशी नस्लें अद्वितीय हैं, जो सभी क्षेत्रों में मौजूद विविधता की विशालता को भी दर्शाती हैं। मानव सभ्यताओं के विकास के समय से पशुपालन ऐतिहासिक रूप से कृषि का अभिन्न अंग रहा है। यह हमारे जैसे देश में और भी प्रासंगिक है, जहां समाज का एक बड़ा वर्ग पशुपालन से सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है और उस पर निर्भर है।

हमारा देश पशु जैव विविधता से समृद्ध

हमारा देश पशु जैव विविधता से समृद्ध है और लोग युगों से विभिन्न प्रकार की प्रजातियों का पालन करते आ रहे हैं। इन प्रजातियों का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों जैसे भोजन, फाइबर, परिवहन, खाद, कृषि उद्देश्यों आदि के लिए किया जाता रहा है। अतीत में, हमारे किसानों ने इन प्रजातियों की कई विशिष्ट नस्लें विकसित की हैं, जो उस जलवायु स्थिति के अनुकूल हैं। वर्तमान में पूरा विश ?व भारत के पशुधन और कुक्कुट क्षेत्र में भारत की विशाल विविधता को देख रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) द्वारा देश में पशु आनुवंशिक संसाधनों का दस्तावेजीकरण करने का प्रयास और उनकी आनुवंशिक विविधता को संरक्षित करने की भी सराहना की गई है।

28 नई पंजीकृत नस्लों के नस्ल पंजीकरण प्रमाण पत्र वितरित किए

इस अवसर पर 28 नई पंजीकृत नस्लों के नस्ल पंजीकरण प्रमाण पत्र वितरित किए गए, जिनमें मवेशियों की 10 नस्लें, सुअर की 5, भैंस की 4, बकरी और कुत्ते की 3-3, भेड़, गधे और बत्तख की एक-एक नस्ल शामिल हैं। डेयर ने वर्ष 2019 से सभी पंजीकृत नस्लों को राजपत्र में अधिसूचित करना शुरू कर दिया है। कार्यक्रम में डीएएचडी, आईसीएआर और इसके संस्थानों के अधिकारी और विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति उपस्थित थे।

-कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को बताया महत्व

रीवा में सरसों उत्पादन के साथ मधुमक्खी पालन

रीवा।

कृषि महाविद्यालय रीवा के अधिष्ठाता प्रो. एसके पयासी के मार्गदर्शन एवं कृषि विज्ञान केंद्र रीवा के प्रमुख प्रो. एके पांडेय के निर्देशन में ग्राम पिपरी, बैकुंठपुर, सिरमौर में मधुमक्खी पालन एवं प्रबंधन पर कृषक प्रशिक्षण और सरसों में प्रक्षेत्र दिवस मनाया गया। डॉ. अखिलेश कुमार पौध संरक्षण वैज्ञानिक केवीके ने बताया कि मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है। सरसों में पर परागण में मुख्य भूमिका निभाती है। जैसा कि सरसों एक उच्च पर परागण की फसल है। इसमें 15 से 20 प्रतिशत उत्पादन मधुमक्खी के परागण के कारण बढ़ने के साथ बीज की गुणवत्ता भी बढ़ जाती है। फसलों एवं फलों में मधुमक्खी से 80 से 85 प्रतिशत पर परागण होता है। साथ ही साथ इससे सह उत्पाद जैसे मधु, रॉयल जेली, प्रोपोलिस, वैक्स, परागकण, विष प्राप्त होता है, जिसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के रोगों में दवाओं में किया जाता है। मधुमक्खी पालन एक उत्तम व्यसाय है जिसमे 10 बॉक्स से मधुमक्खी पालन की शुरुआत करने से प्रति वर्ष लगभग 150000 से 200000 रुपए की आय प्राप्त होती है। साथ फसलों की उत्पादकता में भी इजाफा होता है।

फसलों को कीट व्याधि से बचाने बताए उपाय

इधर, कृषि विज्ञान केंद्र रीवा के प्रमुख प्रो. एके पांडेय के निर्देशन में ग्राम खोखम, निपनिया में लगी जौ, मसूर, सरसों, चना, अलसी और गेहूं की फसल का केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा निरीक्षण करके प्रशिक्षण दिया गया। डॉ. अखिलेश कुमार पौध संरक्षण वैज्ञानिक केवीके ने कृषकों को बताया कि इस समय सरसों, मसूर में माहू और प्याज में थ्रीप्स का प्रकोप है। इसके नियंत्रण के लिए थियोक्लोप्रिड की 8 मिली मात्रा प्रति टंकी और चने में इल्ली के प्रकोप होने पर इंडोक्साकार्ब 15.8 ईसी की 15 मिली मात्रा प्रति टंकी डालकर छिड़काव करें। सस्य वैज्ञानिक डॉ. स्मिता सिंह ने रबी की फसलों में अधिक उत्पादन के लिए सिंचाई, सूक्ष्म पोषक तत्व के उपयोग और प्रबंधन पर जानकारी दी। मौसम वैज्ञानिक मंजू शुक्ला ने आजकल मौसम में हो परिवर्तन का फसलों पर पड़ने वाले बुरे प्रभाव से बचाने के लिए किसानों को बताया।

किसानों को किया जागरुक | मधुमक्खी का पौधो एवं प्राणियों में महत्व पर एक बार वैज्ञानिक अल्बर्ट आईस्टीन ने कहा था कि अगर इस धरती से मधुमक्खियां विलुप्त हो जाएं तो विश्व में मानव का अस्तित्व केवल चार वर्षों तक ही संभव हो सकेगा। क्योंकि अगर मधुमक्खियों का अस्तित्व संकट में होगा तो फसलों में परागण नहीं होगा। पौधों, जानवरों और मनुष्यों की प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी। इस अवसर पर कृषकों को स्वच्छता प्रबंधन पर जागरूक किया गया। इस अवसर गांव के प्रगतशील मधुमक्खी पलक अरुण कुमार द्विवेदी उपस्थित थे।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत मिलेगा लाभ

किसानों को तारबंदी के लिए सरकार दे रही है सब्सिडी

जागत गांव हमार, भोपाल।

जंगली जानवरों और अवारा पशुओं से फसल को बचाने के लिए मप्र सरकार के उद्यानिकी विभाग ने चयनित जिलों के विकास खंडों में चैनलिंक फैसिंग पर अनुदान देने के लिए लक्ष्य जारी किया है। जिसके लिए 13 फरवरी से आवेदन शुरू है। उद्यानिकी विभाग ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वर्ष 2021-22 के अंतर्गत राज्य के 20 जिलों के मॉडल विकासखंड के किसानों के लिए लक्ष्य जारी किए हैं। इन जिलों के किसान मप्र उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं।

इनको मिलेगा लाभ: मप्र उद्यानिकी विभाग ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2021-22 के तहत राज्य के उज्जैन जिले के महिदपुर, शाजापुर जिले के शुजालपुर, सिहोर जिले के नसरूल्लागंज, होशंगाबाद जिले के होशंगाबाद, मंडला जिले के नारायणगंज, ग्वालियर जिले के मुरार, बालाघाट के परसवाडा, दतिया के सेवढा, शिवपुरी के करेरा, बड़वानी के पाटी, सतना के रामपुर बघेलान, छतरपुर जिले के राजनगर, उमरिया के पाली, रीवा के रीवा, दमोह के पथरिया, पन्ना के अजयगढ़, मुरैना के पोरसा, झाबुआ जिले के झाबुआ, जबलपुर जिले के कुंडम एवं भोपाल जिले के बैरसिया विखं के लिए लक्ष्य जारी किए गए हैं।

आवेदन कहाँ करें: योजना का लाभ लेने के लिए उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, मप्र के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

आवश्यक दस्तावेज: आवेदन करते समय फोटो, आधार, खसरा नम्बर/बी1/ पट्टे की प्रति, बैंक पासबुक, जाति प्रमाण पत्र आदि आदि दस्तावेज लगेंगे। ऑनलाइन पंजीयन उद्यानिकी विभाग मध्यप्रदेश फार्मर्स सब्सिडी ट्रैकिंग सिस्टम https://mpfsts.mp.gov.in/ mphd/#/ पर जाकर करना होगा।

जागत गांव हमार के सुधि पाठकों...

» जागत गांव हमार कृषि, पंचायत और ग्रामीण विकास आधारित समाचार पत्र है, जिसके लिए आपका स्नेह और प्यार हमें शुरू से मिलता रहा है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आगे भी मिलता रहेगा।

» समाचार पत्र के लिए विशेषज्ञों की राय, प्रकाशन योग्य सामग्री के साथ-साथ आपके समक्ष इसे पहुंचाने तक हमारी जिम्मेदारी बड़ी चुनौतीपूर्ण है। आपके सहयोग से ही हम इस चुनौती का सामना कर पाएंगे।

» ऐसे में हमारी आपसे अपेक्षा और आग्रह है कि जागत गांव हमार के वार्षिक सदस्य बनें और इसके लिए नीचे लिखे गए नंबर पर संपर्क करें।

संपर्क करें- अजय द्विवेदी-9229497393, 94250485889

"आपका सहयोग हमारी मजबूती का आधार बनेगा"

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादक: अजय कुमार द्विवेदी, स्थानीय संपादक- **अरविंद मिश्र, संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेल:- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)